विचार बिन्दु

दूसरों के अनुभव से होशियारी सीखने की मनुष्य को इच्छा नहीं होती, उसको स्वतंत्र ठोकरें चाहिए। –विनोबा

क्या चुनाव जीतना ही सब कुछ है?

देश में कुछ वर्षों से जो हो रहा है, उसे देखकर तो यह लगता है कि राजनीतिक दलों के लिए जनता एवं उसका हित कोई मायने नहीं रखता एवं उनके लिए केवल एक ही लक्ष्य है और वह है चुनाव जीतना। चुनाव जीतने के लिए यदि उन्हें अपने मूल्यों की बलि चढ़ानी पड़े या गरिमा को तार-तार करना पड़े, अथवा देश में वैमनस्य का वातावरण फैलाना पड़े तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता है।

इसे हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे।

गत कुछ दिनों से उर्दू भाषा को लेकर विवाद उत्पन्न किया जा रहा है। इसे मुसलमानों और आक्रांताओं की निशानी बता कर इस पर निशाना साधा जा रहा है। उर्दू को गुलामी का प्रतीक बता देने वाले यह भूल जाते हैं कि उर्दू किसी मुस्लिम देश की भाषा है ही नहीं, यह हर हिन्दुस्तानी की भाषा है। स्वतंत्रता के बाद अब पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी उर्दू बोली जाती है। उर्दू को भारत में कई बार देवनागरी लिपि में ही लिखा जाता है। शायद ही कोई हिंदी का विद्वान होगा, जो अपने लेखन में अथवा अपने वक्तव्य में, उर्दू का प्रयोग जाने-अनजाने नहीं करता होगा। आजकल, जो लोग उर्दू का विरोध करते हुए वक्तव्य दे रहे हैं, यदि उनका विश्लेषण कर लिया जाए, तो पाएंगे कि उनमें ही उर्दू के कई शब्द शामिल हैं। उर्दू और हिंदी इस प्रकार से घुल-मिल गई है जैसे पानी में नमक अथवा चीनी घुल जाती है। हम जिस भाषा में सामान्यत: बातचीत करते हैं उनमें भी अनेक शब्द उर्दू के सम्मिलित हैं। यहां तक कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भाजपा के नेता भी अपने भाषणों में कुछ उर्दू शब्दों का प्रयोग करते हैं। कई बार वे अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए उर्दू की शेरो-शायरी का उपयोग भी करते हैं। इस प्रकार जो भाषा यहां के सामान्य बोलचाल की भाषा बन चुकी है, उस पर विवाद उत्पन्न करने का उद्देश्य समाज में ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतना ही लगता है।

भारत के शहरों और गांवों में हिंदुओं और मुसलमानों की अंतर निर्भरता इतनी अधिक है कि उन्हें एक दूसरे से अलग करना संभव ही नहीं है। विभिन्न हिंदू त्योहारों और उत्सवों पर काम आने वाली विभिन्न वस्तुओं का निर्माण मुसलमान कारीगरों द्वारा किया जाता है, चाहे वह बंधेज की साडी हो, लाख की चूडियां हो, विभिन्न प्रकार की नक्काशी का काम हो, रजाई बनाने का काम हो। अच्छी मेहंदी लगाने वाली अधिकांश लडकियां मुस्लिम परिवारों से आती हैं। होली पर एक-दूसरे पर फेंके जाने वाले गुलाल घोटे भी अधिकांशतया मुस्लिम ही बनाते हैं। संक्रांति के अवसर पर उडने वाली पतंगें और मांझा मुस्लिम परिवारों द्वारा बनाए जाते हैं। दिवाली पर आतिशबाजी का जिम्मा भी अक्सर मुसलमानों का ही होता है। अत:, हिंदू-मुसलमानों को एक-दूसरे के विरुद्ध खडा करने का उद्देश्य केवल वोट पाना ही हो सकता है।

सदियों से हिंदू-मुसलमान एक ही घर के सदस्यों की तरह मिलजुल कर प्रेम से रहते आए हैं। जहां मुसलमान, नमाज पढ़ने के बाद हिंदू भाइयों के साथ आराम से होली खेलते हैं, वहीं हिंदू, ईद के अवसर पर ईदी खाने में कोई संकोच नहीं करते थे। इसी परम्परा को तो गंगा-जमनी विरासत का नाम दिया गया है। यही हर भारतीय के स्वभाव में रचा बसा है, चाहे वह हिंदू हो या मुसलमान।

इस समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा को दोनों पक्षों के कुछ कट्टरपंथियों द्वारा इसलिए तोड़ा जा रहा है ताकि इसके आधार पर समाज में विभाजन किया जा सके और अपने वोटो की खेती को बढ़ाया जा सके।

हाल ही में संभल में जिस प्रकार होली के दिन मस्जिदों को ढक कर, होली का त्यौहार मनाया गया, वह सामान्य नहीं था। उत्सवों पर रैपिड एक्शन फोर्स और सीआरपीएफ की तैनाती करने का लक्ष्य केवल सांप्रदायिक भय का वातावरण बनाकर एक-दूसरे वर्ग के प्रति दुर्भावना उत्पन्न कर चुनाव जीतना होता है। चुनाव जीतने के लिए इन तरीकों का सहारा लेने वाले यह भूल जाते हैं कि इससे होने वाला नुकसान वर्षों तक समाज को भुगतना पडेगा। जब समाज में इस प्रकार से शंका के बीज बोए जाएंगे, तो इसकी परिणति अंतत: समाज में विभाजन को और गहरा करने के रूप में ही होगी। यह आजकल होने भी लगा है। हर छोटी-छोटी बात को साम्प्रदायिक उन्माद को बढ़ाने के लिए काम में लिया जा रहा है।

चुनाव जीतने के लिए सरकार नागरिकों के मूल अधिकारों का हनन करने से भी नहीं चूकती। उदाहरण के लिए, सूचना का अधिकार कानून इसलिए लाया गया था कि सरकार के कामकाज में पारदर्शिता आ सके और लोगों को पता लग सके कि उनसे संबंधित कार्यों को किस प्रकार किया जा रहा है। आजकल, प्रधानमंत्री की डिग्री का मामला तूल पकडता जा रहा है। जब मुख्य सूचना आयुक्त ने डिग्री दिखाने का आदेश दिया तो उसकी पालना नहीं की गई। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री की कथित डिग्री को अमित शाह और अरुण जेटली द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबके समक्ष दिखाया गया था। क्या न्यायालय द्वारा यह आदेश पारित नहीं किया जा सकता कि जब सार्वजनिक रूप से उनकी डिग्री को स्वयं भाजपा के नेताओं ने प्रेस के समक्ष दिखा दिया तो उसकी मूल प्रति मांग ली जाए और उसका सत्यापन संबंधित विश्वविद्यालय से करा लिया जाय? यहां प्रश्न यह नहीं है कि प्रधानमंत्री की पढ़ाई कितनी हुई है? कानूनन प्रधानमंत्री बनने के लिए कोई न्यूनतम योग्यता निर्धारित नहीं है। प्रश्न केवल यह है कि क्या चुनाव के लिए फॉर्म भरते समय गलत जानकारी दी गई? जनता को वास्तविकता जानने का अधिकार तो है ही। इस बारे में स्थिति स्पष्ट करने के स्थान पर, अब सूचना के अधिकार कानून में ही संशोधन करने की बात कही जा रही है ताकि न्यायालय भी प्रधानमंत्री की डिग्री संबंधित कोई आदेश नहीं दे सके। इस कारण नागरिकों को सही जानकारी उपलब्ध कराने के स्थान पर उन्हें सूचना के अधिकार से ही वंचित किया जा रहा है। क्या ऐसा करना उचित कहा जा सकता है?

राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव जीतने के लिए तथाकथित धर्म गुरुओं और बाबाओं का भी सहारा लिया जाता है। इसके लिए चाहे बलात्कार और हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे आसाराम बापू और बाबा गुरमीत राम रहीम को चुनाव के समय पैरोल पर ही क्यों न छोड़ना पड़े? सरकारों की यह कार्यवाही यही सिद्ध करती है कि राजनैतिक दलों के लिए चुनाव जीतना ही एकमात्र लक्ष्य है।

कोरोना के दौरान पीएम केयर फंड में अरबों रुपए की राशि विभिन्न स्त्रोतों से प्राप्त हुई। इसका कहां और कैसे उपयोग हुआ ,आज तक किसी को पता नहीं है। संभव है, तकनीकी रूप से इसका कैग (सी ए जी) द्वारा अंकेक्षण का प्रावधान न हो, किंतु स्वयं सरकार को क्या यह नहीं चाहिए कि वह प्राप्त धनराशि का हिसाब देश के समक्ष प्रस्तुत करे ताकि जनता आश्वस्त हो सके कि इसका दुरुपयोग कहीं अपने चुनावी लाभ के लिए तो नहीं किया गया?

यही स्थिति इलेक्टोरल बॉन्ड की भी थी। यह तो भला हो सुप्रीम कोर्ट का कि उसने इलेक्टरल बॉन्ड के संबंध में जानकारी सार्वजनिक करने हेतु सरकार को बाध्य किया और इस योजना को अपारदर्शी मानते हुए इसे निरस्त भी कर दिया।

चुनाव जीतने के लिए समाज को विभाजित करने के काम में विपक्षी दल भी पीछे नहीं हैं। जातिगत गणना की मांग करके वे देश को जातियों में बांटने का ही तो काम कर रहे हैं। इसका मुख्य उद्देश्य विभिन्न जातियों में एक दूसरे के प्रति कटुता और विद्वेष उत्पन्न करना ही तो है ताकि जाति गत ध्रुवीकरण से अधिकाधिक मत प्राप्त कर सकें। होना तो चाहिए कि सबको अच्छी शिक्षा के अवसर उपलब्ध हों और चयन जाति के आधार पर नहीं अपितु केवल योग्यता के आधार पर हो। आरक्षित वर्ग में क्रीमी लेयर को आरक्षण न देने की बात तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कही है। हाल ही में कर्नाटका सरकार ने सरकारी ठेकों में मुस्लिमों के लिए 4 प्रतिशत आरक्षण बात भी इसी प्रकार का विभाजन कारी कदम है जिसका उद्देश्य केवल अल्पसंख्यकों के मत प्राप्त करना है।

राजनीतिक दलों द्वारा चुनाव जीतने के लिए तथाकथित धर्म गुरुओं और बाबाओं का भी सहारा लिया जाता है। इसके लिए चाहे बलात्कार और हत्या के आरोप में आजीवन कारावास की सजा भुगत रहे आसाराम बापू और बाबा गुरमीत राम रहीम को चुनाव के समय पैरोल पर ही क्यों न छोडना पडे? सरकारों की यह कार्यवाही यही सिद्ध करती है कि राजनैतिक दलों के लिए चुनाव जीतना ही एकमात्र लक्ष्य है। इसके लिए राजनीतिक दलों और नेताओं को बलात्कारी और पाखंडी बाबाओं का सहयोग लेने में भी कोई शर्म नहीं है। यह सबका संवैधानिक दायित्व है कि समाज में वैज्ञानिक सोच को विकसित किया जाए। इसके बावजूद, नेताओं द्वारा पाखंडी बाबाओ के माध्यम से अंधविश्वास को फैलाया जाए और उसके आधार पर समाज का विभाजन करके समर्थन जुटाया जाए ताकि चुनाव में जीत हासिल की जा सके, तो इसे देश का दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। जिस बागेश्वर बाबा उर्फ धीरेन्द्र शास्त्री ने कुंभ के दौरान भगदड में मरने वालों के मोक्ष प्राप्त करने की बात कही हो, उन्हीं के चरणों में यदि प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और अन्य प्रमुख नेता आशीर्वाद लेने चले जाएं तो इससे अंध विश्वास ही तो बढ़ेगा। सबका उद्देश्य केवल मात्र चुनाव जीतना है।

किस प्रकार धर्म के नाम पर समाज को विभाजित किया जा रहा है वह इन नारों से ही स्पष्ट है, जैसे 'एक है तो सेफ है' 'बटेंगे तो कटेंगे'। योगी जी मुसलमान के लिए 'कठमुल्ला' शब्द का प्रयोग करते हैं, किंतु ऐसा करते समय वे यह भूल जाते हैं कि कठमुल्ला का कोई संबंध 'मुल्ला' से नहीं है। इसका प्रयोग अज्ञानी व्यक्ति के लिए किया जाता है। यह सब केवल धार्मिक भावनाओं को भडकाने के लिए किया जाए तो इसे 'विकसित भारत' की निशानी तो नहीं माना जा सकता।

शिक्षा की दुर्गति जो कुछ वर्षों में हुई है उससे सभी परिचित हैं। इसी प्रकार आपाधापी में चुनाव से पूर्व अनेक विद्यालय, महाविद्यालय और विश्वविद्यालय खोल दिए जाते हैं। इनमें न शिक्षक हैं न आधार भूत सुविधाएं। यहां तक कि मेडिकल कॉलेज भी बिना शिक्षकों के खोल दिए गए। एक-एक कमरे में महाविद्यालय चल रहे हैं। इस प्रकार के निर्णय लेते समय जनता का हित गौण हो जाता है। यह जनता के साथ छलावा ही है। प्रारंभिक शिक्षा की गुणवत्ता तो गर्त में चली गई है। शिक्षा की किसी को परवाह नहीं है, क्योंकि इसके आधार पर चुनाव नहीं जीते जाते। स्पष्ट है, सबका उद्देश्य चुनाव जीतना ही है।

एक जागरूक समाज की निशानी है कि उसके सदस्य सत्ता से सवाल करने का साहस रखें। किंतु यदि सत्ता ही सवाल पूछने वालों को प्रताडित करे अथवा जेल भेज दे, केवल इसलिए कि उनका चुनावी नुकसान न हो, तो इसे स्वस्थ संकेत नहीं कहा जा सकता।

कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि आजकल चुनाव जीतना ही एकमात्र लक्ष्य हो गया है, चाहे इसके लिए झूठ बोलना पडे, जनता को धोखा देना पडे, लोगों को झूठे आश्वासन देने पड़ें, समाज का ध्रुवीकरण ही क्यों न करना पडे।

इस स्थिति को बदलना आवश्यक है। और जितना यह कार्य शीघ्र किया जाए उतना ही उत्तम होगा।

प्रश्न यह है कि आखिर कब तक केवल चुनावी जीत के लिए सामाजिक समरसता, भाईचारा, ईमानदारी, कर्तव्य, निष्ठा, देश प्रेम, परस्पर सद्भाव की विरासत, छिन्न-भिन्न होती रहेगी तथा हमारे लोकतंत्र और राष्ट्र को भीतर ही भीतर खोखला करती रहेगी?

–अतिथि सम्पादक,
राजेन्द्र भाणावत
(पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी)

विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक मूल्यांकन में बड़ा बदलाव : चुनौतियां और समाधान

अशोक कुमार

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, यूजीसी ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है जो भारतीय विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक परिदृश्य को नया आकार दे सकता है। इस निर्णय के तहत यूजीसी ने संकाय मूल्यांकन के लिए संशोधित मानदंड पेश किए हैं। इसका उद्देश्य शिक्षण संस्थानो और शिक्षकों के मूल्यांकन के लिए अधिक व्यापक और समग्र दृष्टिकोण अपनाना है। ये परिवर्तन पहले के मानकों से एक महत्वपूर्ण बदलाव को दर्शाते हैं, जिसमें शोध प्रकाशनों और प्रदर्शन-आधारित अंकों पर बहुत अधिक जोर दिया जाता था।

नए अकादमिक प्रदर्शन संकेतक ढांचे में विस्तृत संशोधित दिशा-निर्देश, विशुद्ध रूप से अकादमिक आउटपुट से ध्यान हटाकर शिक्षण प्रभावशीलता, छात्र प्रतिक्रिया और संस्थागत योगदान के व्यापक दृष्टिकोण पर केंद्रित करने के लिए तैयार हैं। पारंपरिक स्कोर-केंद्रित प्रणाली को अधिक गुणात्मक मूल्यांकन से बदला जा रहा है जिसमें विभिन्न प्रकार के प्रदर्शन क्षेत्र शामिल हैं।

नया ढांचा छात्र प्रतिक्रिया, मार्गदर्शन और सीखने के परिणामों को ध्यान में रखेगा। आउटरीच कार्यक्रमों, सामाजिक परियोजनाओं और संस्था-निर्माण गतिविधियों में शिक्षकों के योगदान को महत्व दिया जाएगा। कक्षा नवाचार, प्रौद्योगिकी का उपयोग और शिक्षार्थियों के साथ जुड़ाव केवल प्रकाशन रिकॉर्ड से अधिक मूल्य रखेगा। जबकि शोध महत्वपूर्ण बना हुआ है, समग्र मूल्यांकन में इसके महत्व को तर्कसंगत बनाया गया है, यह मानते हुए कि सभी संकाय भूमिकाएँ शोध-गहन नहीं हैं।

यूजीसी ने स्वीकार किया है कि पहले के मेट्रिक्स ने प्रकाशन को असमान रूप से पुरस्कृत किया, अक्सर सार्थक शिक्षण की कीमत पर। इस नए मॉडल में बदलाव करके प्रणाली अधिक समावेशी और निष्पक्ष हो जाती है, विशेष रूप से गैर-शोध-गहन भूमिकाओं में शिक्षकों के लिए। संकाय छात्र परिणामों, शिक्षण पद्धति और वास्तविक दुनिया के प्रभाव पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के व्यापक दृष्टिकोण के साथ संरेखित है, जो शिक्षा की गुणवत्ता के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण को बढ़ावा देता है। यह नया ढांचा संकाय को केवल शोधपत्रों के प्रकाशक से अधिक होने के लिए प्रोत्साहित करता है। यह कक्षा को प्रभाव के लिए प्राथमिक स्थान के रूप में मान्यता देता है। अन्य लोगों ने उल्लेख किया है कि यह दृष्टिकोण वैश्विक विश्वविद्यालय प्रणालियों के अनुरूप है, जहाँ शिक्षण उत्कृष्टता को अनुसंधान के समान ही महत्व दिया जाता है। इन मानदंडों को सभी यूजीसी-संबद्ध और केंद्र द्वारा वित्तपोषित संस्थानों में लागू किए जाने की उम्मीद है। शोध प्रकाशन अभी भी मायने रखेंगे , लेकिन उनका महत्व शिक्षण और सामुदायिक जुड़ाव जैसे अन्य योगदानों के साथ संतुलित किया जाएगा। नए मूल्यांकन मानदंड हालाँकि आधिकारिक तिथि की घोषणा नहीं की गई है, लेकिन उन्हें 2025 से चरणों में अपनाए जाने की उम्मीद है। ये परिवर्तन पदोन्नति और कैरियर की प्रगति शिक्षक के समग्र योगदान से अधिक निकटता से जुड़ी होगी।

यूजीसी ने समग्र शिक्षक मूल्यांकन मानदंड पेश किए हैं, जिसका उद्देश्य शिक्षकों के प्रदर्शन का अधिक व्यापक और निष्पक्ष मूल्यांकन करना है। हालांकि, इस नए मानदंड के कार्यान्वयन में कुछ चुनौतियां और समस्याएँ हैं।

नए मानदंड में छात्रों, सहकर्मियों और स्वयं के मूल्यांकन सहित कई कारकों को शामिल किया गया है। इससे मूल्यांकन में व्यक्तिपरकता का खतरा बढ़ जाता है, क्योंकि विभिन्न व्यक्तियों के अलग-अलग दृष्टिकोण हो सकते हैं। शिक्षकों को अपने प्रदर्शन का विस्तृत दस्तावेजीकरण करने और कई मूल्यांकनकर्ताओं से प्रतिक्रिया एकत्र करने की आवश्यकता होगी। इससे शिक्षकों पर अतिरिक्त प्रशासनिक बोझ बढ़ सकता है। शिक्षकों और मूल्यांकनकर्ताओं को नए मानदंडों को समझने और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए पर्याप्त प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। विभिन्न संस्थानों में मूल्यांकन प्रक्रियाओं में एकरूपता सुनिश्चित करना एक चुनौती हो सकती है।

नए मानदंड के कार्यान्वयन में कुछ समस्याएँ भी हैं। लगातार मूल्यांकन का डर शिक्षकों में तनाव और चिंता पैदा कर सकता है, जिससे उनकी रचनात्मकता और शिक्षण की गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है। यदि मूल्यांकन पर अत्यधिक ध्यान दिया जाता है, तो शिक्षक नवाचार और जोखिम लेने के बजाय केवल अच्छे अंक प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। अनैतिक व्यवहार को प्रोत्साहन को बढ़ावा मिलने की आशा है। कुछ शिक्षक बेहतर मूल्यांकन प्राप्त करने के लिए अनैतिक व्यवहार का सहारा ले सकते हैं, जैसे कि छात्रों को अच्छे अंक देने के लिए दबाव डालना या सहकर्मियों को प्रभावित करना। मूल्यांकन प्रक्रिया में बहुत अधिक समय लगने से शिक्षकों को अपने शिक्षण कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई हो सकती है।

विभिन्न चुनौतियां और समस्याएँ के समाधान के लिए मूल्यांकनकर्ताओं को निष्पक्ष और वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन करने के लिए प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। मूल्यांकन प्रक्रिया स्पष्ट, पारदर्शी और सभी हितधारकों के लिए सुलभ होनी चाहिए। शिक्षकों को उनके प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए नियमित रूप से समर्थन और प्रतिक्रिया प्रदान की जानी चाहिए। मूल्यांकन प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने और प्रशासनिक बोझ को कम करने के लिए तकनीक का उपयोग किया जा सकता है।यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि समग्र शिक्षक मूल्यांकन मानदंड एक सकारात्मक कदम है, लेकिन इसके सफल कार्यान्वयन के लिए इन चुनौतियों और कमियों को दूर करना आवश्यक है।

–अशोक कुमार,
पूर्व कुलपति कानपुर,
गोरखपुर विश्वविद्यालय,
विभागाध्यक्ष राजस्थान
विश्वविद्यालय जयपुर

8.97 करोड़ के गबन के विरोध में 20 खाताधारक पानी की टंकी पर चढ़े

मामला जैतसर के 3 जीबी ग्राम सेवा सहकारी समिति मिनी बैंक का है

श्रीगंगानगर, (निसं)। बैंक में हुए करीब नौ करोड़ के गबन के विरोध में 20 खाताधारक पानी की टंकी पर चढ़ गए। इनमें चार महिलाएं भी हैं। मामला जैतसर के 3 जीबी ग्राम सेवा सहकारी समिति मिनी बैंक का है। ये लोग श्रीकृष्ण गोशाला के पास श्मशान घाट में बनी ओवरहेड टंकी पर चढ़े हैं। इनकी मांग है कि सभी अकाउंट होल्डर को उनके पैसे मिलने चाहिए। आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए और उनकी संपत्ति कुर्क की जाए।

जानकारी के अनुसार अक्टूबर 2024 में जांच के दौरान बैंक में 8.97 करोड़ रुपए के गबन का मामला सामने आया था। जांच में पाया गया कि यह सिलसिला साल 2014 से चल रहा था। जांच के दौरान 444 खाताधारकों से जानकारी प्राप्त की गई, जिनकी कुल जमा पूंजी 9.75 करोड़ रुपए थी, लेकिन कुछ खाताधारक अब भी अपनी जानकारी देने के लिए उपस्थित नहीं हो पाए हैं, जिसके कारण जांच अब भी जारी है। भूमि विकास बैंक के पूर्व अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह रंधावा टंकी पर चढ़े लोगों का समर्थन कर रहे हैं। उन्होंने ओवरहेड टैंक से एक वीडियो जारी किया।

उन्होंने कहा कि किसी ने बच्चे की शादी, किसी ने बिजनेस शुरू करने तो किसी ने मकान बनाने के लिए बैंक में पैसे जमा किए थे। गांव की एक महिला है, उसके पति की करंट की चपेट में आने से मौत हो गई थी। उसे पांच लाख का मुआवजा मिला था। उसने भविष्य में बेटियों की शादी के लिए बैंक में पैसे जमा कराए थे। आज उसके पास शादी के लिए एक पैसा भी नहीं है। इंद्रजीत रंधावा ने सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक और जिला कलेक्टर डॉ. मंजू से गुजारिश की है कि सरकार से इनको पैसा दिलवाया जाए। रंधावा ने आरोप लगाया कि सरकार ने 200 करोड़ का ब्याज माफ कर दिया, लेकिन ये तो हक के पैसे मांग रहे हैं, इनको पैसा मिलना चाहिए। रंधावा ने चेतावनी देते हुए कहा कि हम यहीं पर बैठे हैं। हम भले ही ऊपर बैठे भूखे मर जाएं, लेकिन हम नीचे तभी आएंगे, जब हमारी मांगें मान ली जाएंगी।

■ लोगों की मांग है कि सभी अकाउंट होल्डर को उनके पैसे मिलने चाहिए, आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए और उनकी संपत्ति कुर्क की जाए

खाताधारक सौरभ मोंगा ने बताया कि बैंक के बाहर धरना-प्रदर्शन को 95 दिन हो चुके हैं। अभी तक हमारी मांगें नहीं मानी गई है। मजबूरन आज पूर्व बैंक अध्यक्ष इंद्रजीत सिंह रंधावा के नेतृत्व में वाटरवर्क्स की ओवरहेड टंकी पर चढ़ना पड़ा। मोंगा ने कहा कि कुछ भी हो जाए, लेकिन जब तक पैसे नहीं मिलेंगे, वो पानी की टंकी से नीचे नहीं उतरेंगे। मोंगा ने दावा किया कि पानी की टंकी पर कुल 30 लोग चढ़े हैं, जिनमें चार महिलाएं भी हैं।

सौरभ मोंगा ने कहा कि हमारी प्रमुख मांग है कि सभी खाताधारकों की पूरी राशि प्रदान की जाए। अभी तक मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। एक की मौत हो चुकी है। तीसरा आरोपी खुलेआम बाहर घूम रहा है। गिरफ्तार आरोपी ओमप्रकाश चुघ की प्रॉपर्टी कुर्क की जाए। पुलिस-प्रशासन के लापरवाह अफसरों को भी सस्पेंड किया जाए। जैतसर पुलिस मौके पर प्रदर्शनकारियों को समझाने का प्रयास कर रही है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक उनकी जमा राशि नहीं लौटाई जाती, तब तक वे टंकी से नीचे नहीं उतरेंगे। स्थानीय प्रशासन और बैंक प्रबंधन की ओर से अभी तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला है। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस-प्रशासन की लापरवाही पर भी सवाल उठाए हैं। उनकी मांग है कि लापरवाह अधिकारियों को निलंबित किया जाए। टंकी के नीचे भी कई खाताधारक धरने में शामिल हैं। सूरतगढ़ के पूर्व विधायक राजेंद्र भादू धरना स्थल पर पहुंचे। जांच अधिकारियों के मुताबिक, बैंक में गबन का मुख्य कारण मियादी जमाओं के खिलाफ अनियमित रूप से ऋण (लोन) वितरण करना था। समिति के कर्मचारियों ने जानबूझकर खाताधारकों की जमा पूंजी को गलत तरीके से ऋण के रूप में वितरित किया।

कई मामलों में मियादी जमा रसीदें मिनी बैंक के रिकॉर्ड में दर्ज नहीं की गई। कई खाताधारकों के नाम पर ऋण वितरित किए गए, जिनके पास मियादी जमा की कोई रसीद ही नहीं थी। जांच के बाद समिति के पूर्व व्यवस्थापक सुमेर सिंह, वर्तमान व्यवस्थापक बिशनपाल सिंह और पूर्व सहायक व्यवस्थापक ओमप्रकाश चुघ को गबन व अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार ठहराया गया। इन अधिकारियों ने अपने पदों का दुरुपयोग किया और बैंक की गबन साजिश में हाथ बढ़ाया। इनमें सुमेर सिंह की मौत हो चुकी है। ओमप्रकाश को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बिशन पाल को अभी तक नहीं पकड़ा है।

पंडेर में झोलाछाप चिकित्सक पर स्वास्थ्य विभाग की कार्रवाई

भीलवाड़ा, (निसं)। जिलेवासियों को सही और सुरक्षित इलाज उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से जिले में अवैध क्लीनिक और झोलाछाप डॉक्टरों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने को लेकर जिले में स्वास्थ्य विभाग की ओर से अभियान जारी है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के आदेशानुसार, ब्लॉक मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अशोक जाट के नेतृत्व में पंडेर कस्बे में बस स्टैण्ड के पास स्थित अवैध नीम हकीम क्लिनिक पर कार्रवाई की गई।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. सीपी गोस्वामी ने बताया कि चिकित्सा विभाग की टीम द्वारा पंडेर कस्बे में कार्रवाई के दौरान वृंदावन नाम के नीम हकीम को मरीजों का इलाज करते हुए पाया गया। झोलाछाप चिकित्सक के पास कोई वैध दस्तावेज नहीं पाए गये। जांच में क्लिनिक पर एलोपैथिक दवाएं, इंजेक्शन व अन्य चिकित्सा उपकरण अवैध रूप से उपयोग किए जा रहे थे। टीम ने मौके पर ही सभी दवाइयां व उपकरण जब्त कर क्लिनिक को सीज कर दिया। इसके साथ ही पुलिस द्वारा झोलाछाप चिकित्सक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की। इस दौरान चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, पंडेर डॉ. राहुल शर्मा, बीपीओ रामजस, फार्मासिस्ट अभिषेक गुर्जर सहित स्वास्थ्य विभाग की टीम के सदस्य मौजूद रहे।

■ स्वास्थ्य विभाग की टीम ने क्लिनिक पर उपलब्ध दवायें व उपकरण जब्त किये

आरपीएससी ने अभ्यर्थियों को संशोधन का अवसर दिया

अजमेर, (कासं)। राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा मई माह में प्रस्तावित विभिन्न परीक्षाओं के अन्तर्गत संशोधन का अवसर अभ्यर्थियों को दिया गया है। आयोग सचिव ने बताया कि भूवैज्ञानिक एवं सहायक खनि अभियंता (खान एवं भूविज्ञान विभाग) परीक्षा, 2024 का आयोजन 7 मई 2025 को, सहायक आचार्य (चिकित्सा शिक्षा विभाग) परीक्षा-2024 (09 विषय) का आयोजन 12 मई से 16 मई तक, वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी (गृह विभाग) परीक्षा 2024 (08 विषय) का आयोजन 12 मई से 16 मई तक एवं जनसम्पर्क अधिकारी (सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग) परीक्षा-2024 का आयोजन 17 मई को करवाया जाना प्रस्तावित है। आयोग द्वारा अभ्यर्थियों को उक्त परीक्षाओं के लिए जारी विज्ञापन में उल्लेखित शर्तों अनुसार 19 मार्च से 25 मार्च तक अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, फोटो, जन्म तिथि व जेंडर के अतिरिक्त अन्य संशोधन ऑनलाइन करने का अवसर दिया जा रहा है। इस संबंध में विस्तृत सूचना आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है। ऑनलाइन संशोधन का अवसर अभ्यर्थियों के हितार्थ सुविधा मात्र है। परीक्षा के लिए जारी विज्ञापन में उल्लेखित पात्रता की शर्तों के अनुरूप ही संशोधन मान्य होंगे। विज्ञापन की शर्तें पूर्वानुसार ही रहेंगी।

■ अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, फोटो, जन्म तिथि, जेंडर के अतिरिक्त प्रविष्टियों में संशोधन कर सकेंगे

राशिफल मंगलवार 18 मार्च, 2025

पंडित अनिल शर्मा

चैत्र मास, कृष्ण पक्ष, चतुरथी तिथि, मंगलवार, विक्रम संवत 2081, स्वाती नक्षत्र सायं 5:52 तक, व्याघात योग सायं 4:44 तक, बव करण प्रात: 8:52 तक, चन्द्रमा आज तुला राशि में संचार करेगा।

ग्रह स्थिति: सूर्य-मीन, चन्द्रमा-तुला, मंगल-मिथुन, बुध-मीन, गुरू-वृष, शुक्र-मीन, शनि-कुम्भ, राहु-मीन, केतु-कन्या राशि में।

आज कुमार योग रात्रि 10:10 से आरम्भ होगा। आज शुक्र वृदत्व 10:10 से आरम्भ होगा।

श्रेष्ठ चौघड़िया: चर 9:36 से 11:06 तक, लाभ-अमृत 11:06 से 2:05 तक, शुभ 3:54 से 5:04 तक। राहूकाल: 3:00 से 4:30 तक। सूर्योदय 6:37, सूर्यास्त 6:33

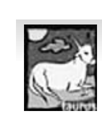

मेष

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक कार्यों में प्रगति होगी। व्यावसायिक आय में वृद्धि होगी। परिवार में आपसी सहयोग-समन्वय बना रहेगा।

सिंह

व्यावसायिक कार्यों के संबंध में तनाव बना रहेगा। नौकरीपेशा व्यक्तियों को उच्चाधिकारियों की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है।

धनु

आर्थिक कारणों से अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। आय में वृद्धि हो सकती है। धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में महत्वपूर्ण कार्य सम्पन्न हो सकते हैं।

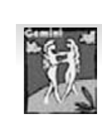

वृष

मित्रों/रिश्तेदारों से चल रहे मतभेद समाप्त होंगे। विवादित मामलों से राहत मिल सकती है। दिनचर्या में सुधार होगा। व्यावसायिक आर्थिक मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा।

कन्या

आर्थिक/वित्तीय मामलों के लिए दिन अच्छा रहेगा। आय में वृद्धि होगी। संभावित धन प्राप्त होगा। व्यावसायिक संपर्क बनेंगे। धार्मिक स्थान की यात्रा संभव है।

मकर

व्यावसायिक कार्यों को प्राथमिकता से करने का प्रयास करें। व्यावसायिक कार्य सुगमता से बनने लगेंगे। व्यावसायिक वार्ता सफल रहेगी। परिवार में स्वास्थ्य संबंधित चिन्ता दूर होगी।

मिथुन

नौकरीपेशा व्यक्तियों को भागदौड़ रहेगी। व्यावसायिक खर्चों पर नियंत्रण रखना ठीक रहेगा। आज महत्वपूर्ण और आवश्यक कार्यों के संबंध में दुविधा बनी रहेगी।

तुला

व्यावसायिक कार्यों पर ध्यान देना ठीक रहेगा। व्यावसायिक प्रयासों में उचित सफलता मिलेगी। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में चल रहा मानसिक तनाव दूर होने लगेगा।

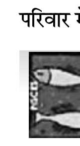

कुंभ

नवीन कार्यों के संबंध में सकारात्मक आश्वासन प्राप्त होंगे। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे। व्यावसायिक/आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में उत्सव जैसा माहौल रहेगा।

कर्क

परिवार में धार्मिक-सामाजिक समारोह सम्पन्न हो सकते हैं। परिवार में सुख-सुविधाएं बढ़ेगी। नौकरीपेशा व्यक्तियों को मानसिक तनाव रहेगा।

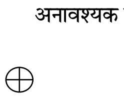

वृश्चिक

स्वास्थ्य संबंधित मामलों में परेशानी हो सकती है। व्यक्तिगत परेशानियां अभी यथावत बनी रहेगी। घर-गृहस्थी के खर्चों में अनावश्यक वृद्धि हो सकती है।

मीन

चन्द्रमा अष्टम भाव में शुभ नहीं है। शुभ कार्यों में व्यवधान सामने आ सकते हैं। आज आवश्यक कार्यों में विलम्ब हो सकता है। बनते कार्य बिगड़ सकते हैं। स्वास्थ्य का ध्यान रखें।